पलविंदर कौर

बनाम

पंजाब राज्य (रूप सिंह-कैविएटर)

[मेहर चंद महाजन, चंद्रशेखर अय्यर, और भगवती जे.जे.]

आपराधिक मुकदमा-परिवेशीय साक्ष्य-संदेह के आधार पर निर्णय के खिलाफ खुद को बचाने के लिए अदालतों का कर्तव्य-स्वीकारोक्ति-को समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए-आत्म-दोषारोपण कथन जिसमें दोषारोपण करने वाले तथ्यों की स्वीकृति होती है-दोषारोपण करने वाले हिस्से को सही के रूप में स्वीकार करना-दोषारोपण करने वाले हिस्से को गलत के रूप में अस्वीकार करना-वैधता-भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 201 - अपराध के आवश्यक तत्व।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में अदालतों को अपने निष्कर्ष को आधार बनाने के खतरे से खुद को बचाना चाहिए। संदेह पर संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो।

रेक्स वी. हॉज (1838) 2 ल्यू 227, और नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1952] एस. सी., आर., 1091 निर्दिष्ट।

भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि कोई अपराध किया गया है (केवल यह संदेह पर्याप्त नहीं है कि यह किया गया है); कि आरोपी पलविंदर कौर को पता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि ऐसा अपराध किया गया था; और यह कि अपेक्षित जानकारी के साथ और अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से आरोपी ने उसके साक्ष्य को गायब कर दिया या ऐसे अपराध के संबंध में गलत जानकारी दी, यह जानते हुए कि या उसे गलत मानने का कारण था। जहां साक्ष्य से पता चलता है कि एक

व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसका शरीर एक ट्रंक में पाया गया था और एक कुएं में पाया गया था और आरोपी ने शरीर के निपटान में भाग लिया था, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण या जिस तरीके या परिस्थितियों में यह हुआ, उसे दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं थाः माना गया कि आरोपी को धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

एक बयान जिसमें आत्म-व्याख्यात्मक विषय शामिल है, एक स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं हो सकता है, अगर दोषमुक्ति का मामला कुछ तथ्य का है, जो अगर सच है तो कथित अपराध को स्वीकार करने के लिए नकारात्मक होगा। एक स्वीकारोक्ति को या तो अपराध के संदर्भ में या कम से कम उन सभी तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए जो अपराध का गठन करते हैं। नारायणस्वामी बनाम सम्राट (1939) 66 आई. ए. 66, संदर्भित।

संस्वीकृति और स्वीकारोक्ति के उपयोग के संबंध में यह एक अच्छी तरह से स्वीकृत नियम है कि इन्हें या तो समग्र रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए या समग्र रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और यह कि अदालत छूट देने वाले हिस्से को स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय के रूप में अस्वीकार करते हुए केवल अपमान करने वाले हिस्से को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है।

सम्राट बनाम बालमुकंद (1930) आई. एल. आर. 52 ऑल 1011

जहां अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान में यह स्वीकार किया गया था कि उसने अपने पति के शव को एक ट्रंक में रखा था और उसे एक जीप में ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया था, लेकिन मृत्यु के कारण के संबंध में उसके द्वारा दिया गया बयान यह था कि उसके पति ने गलती से एक जहरीला पदार्थ ले लिया था जो फोटो धोने के लिए था और उसे गलती से एक दवा समझते हुएः आयोजित, समग्र रूप से पढ़ा गया बयान

चरित्र में दोषमुक्त था और पूरा बयान सबूत में अस्वीकार्य था और उच्च न्यायालय ने इसके पहले हिस्से को स्वीकार करने और बाद वाले हिस्से को गलत मानते हुए गलत तरीके से कार्य किया।

पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 1952 की आपराधिक अपील सं. 41

सत्र न्यायाधीश, शिमला के न्यायालय द्वारा मुकदमा नंबर 1950 का 23 और 1951 का 2 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 31 जनवरी, 1951 के विरुद्ध दायर आपराधिक अपील संख्या 1951 की 86 में पंजाब उच्च न्यायालय, अंबाला (भंडारी और सोनी जे. जे.) के 3 अक्टूबर, 1951 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी के लिए जय गोपाल सेठी (उनके साथ आर. एल. कोहली).

प्रतिवादी के लिए एच. एस. गुजराल।

भगत सिंह चावला, कैविएटर के लिए।

22 अक्टूबर 1952

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

महाजन जे.

पलविंदर कौर पर, उनके पति, यशपाल सिंह की हत्या के संबंध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 201 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। उसे सेशन न्यायाधीश द्वारा धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन परिवहन की सजा सुनाई गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप के संबंध में कोई फैसला दर्ज नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय में अपील करने पर

उन्हें हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष अवकाश द्वारा उनकी अपील अब हमारे सामने है।

जसपाल सिंह, मृतक, भरेली (पंजाब) के मुखिया का बेटा था। उनकी शादी कुछ साल पहले पलविंदर कौर से हुई थी और उनके दो बच्चे थे। पति-पत्नी अंबाला के भरेली स्थित घर में एक साथ रह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जे. असपाल के अपने पिता और दादा के साथ संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं थे और दोनों बुजुर्गों ने सोचा कि इसके लिए पलविंदर कौर जिम्मेदार थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि जसपाल अपने पिता से मिले भत्ते पर जीते थे और दूध और अंडे बेचकर और कुछ अजीबोगरीब काम करके अपनी आय में वृद्धि करते थे। मोहिंदरपाल सिंह (न्याय से भगोड़ा) जो अपीलार्थी से संबंधित है और बलदेवनागा·कैम्प, अंबाला में एक चरवाहे के रूप में कार्यरत था, कभी-कभी भरेली के घर में रहता था। ऐसा माना जाता है कि उसने पलविंदर के साथ संपर्क शुरू किया था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी और मोहिंदरपाल ने 6 फरवरी, 1950 की दोपहर को सरदार जसपाल को पोटेशियम साइनाइड का जहर पिलाया था। इसके बाद शव को एक बड़े ट्रंक में डाल दिया गया और अंबाला शहर में घर के एक कमरे में रख दिया गया। लगभग दस दिन बाद, यानी 16 फरवरी, 1950 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति में, मोहिपदारपाल ने एक जीप में घर से ट्रंक को हटा दिया, जब वह वहां अमृत सिंह और एक कर्तार सिंह (पीडब्ल्यूएस) के साथ आए, जो बलदेव-द स्टेट ऑफ नगर कैंप के दो वाटरमैन थे। इसके बाद ट्रंक को बलदेवनगर कैंप ले जाया गया और वहां एक स्टोर रूम में रखा गया। तीन दिन बाद, 19 फरवरी, 1950 को मोहिंदरपाल ने पलविंदर और एक घरेलू नौकर त्रिलोक चंद (पी. डब्ल्यू. 27) के साथ राजपुरा की ओर जाने वाली सड़क पर कुछ मील की दूरी पर ट्रंक लिया, एक कच्ची

सड़क पर चढ़ गए और गाँव छत के आसपास जीप को एक टीले पर किसी कुएं पर ले गए और उस कुएं में डिब्बा फेंक दिया। जीप को एक गुरुद्वारे में ले जाया गया जहाँ उसे धोया गया।

मृतक के लापता होने के बाद, उसके पिता ने मोहिंदरपाल से उसके लापता बेटे मोहिंदरपाल के ठिकाने के बारे में पूछताछ की ता उसने कई झूठे बयान दिए। 8 मार्च, 1950 को पिता ने "डेली मिलाप" में विज्ञापन देकर अपने बेटे से जल्द से जल्द घर लौटने की गुहार लगाई क्योंकि उसकी अनुपस्थिति के कारण उसकी पत्नी और बच्चों और माता-पिता की हालत दयनीय हो गई थी।

10 मार्च, 1950 को, यानी कथित हत्या के एक महीने और दस दिन बाद और ट्रंक को कुएं में फेंकने के 19 दिन बाद, कुएं से दुर्गंध आ रही थी, और मामले की सूचना गांव छत के लाम्बारदारों को दी जा रही थी, ट्रंक को बाहर निकाला गया था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और 11 मार्च को पुलिस के उप-निरीक्षक सरदार बंता सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और जांच रिपोर्ट तैयार की और डॉक्टर को भेजी। अगले दिन घटनास्थल पर पोस्टमार्टम किया गया। शव की कोई तस्वीर नहीं ली गई और उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी गई। ढाई महीने से अधिक समय के बाद 28 अप्रैल, 1950 को अपीलार्थी और मोहिंदरपाल के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और 26 जून को दोषी मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान पेश किया गया। मोहिंदरपाई का पता नहीं चल सका था और मामला अकेले अपीलार्थी के खिलाफ शुरू किया गया था।

यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अपीलार्थी या मोहिंदरपाल या दोनों ने जसपाल को पोटेशियम साइनाइड दिया और हत्या के संबंध में साक्ष्य विशुद्ध रूप से परिस्थितिजन्य है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त

किया कि मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत था, और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के खिलाफ मामला किसी भी उचित संदेह से परे साबित हुआ था। अपील पर उच्च न्यायालय एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा। इसने माना कि हालांकि कुएं से मिला शव पहचान करने में सक्षम नहीं था, लेकिन ट्रंक से बरामद और शरीर पर पाए गए कपड़ों से साबित होता है कि यह जसपाल का शव था। इसने आगे कहा कि मामले में दिए गए चिकित्सा साक्ष्य से मृत्यु के कारण का पता नहीं चल सका है। शव की पहचान के सवाल पर सबूत में कांस्टेबल लछमन सिंह का बयान, ट्रंक के अंदर से बरामद कपड़े और अन्य सामान और आरोपी के कथित कबूलनामे शामिल थे। साक्ष्य के पहले टुकड़े के संबंध में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राय व्यक्त कीः -

> "हमारी राय में इस तर्क में काफी बल है कि न केवल पैदल सिपाही लछमन सिंह और सहायक उप-निरीक्षक बंता सिंह उन तथ्यों की गवाही दे रहे हैं जो उनकी जानकारी में गलत हैं, बल्कि यह कि अभियोजन पक्ष जानबूझकर एक झूठे गवाह को पेश करने और अन्य गवाहों से लछमन सिंह द्वारा सुनाई गई कहानी का समर्थन करने के लिए कहने के लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने 11 मार्च को शव की पहचान राजपाल सिंह की होने की पहचान की और अगले दिन मृतक के पिता को जानकारी दी।
>
> जहाँ तक मृतक के पिता और दादा, सरदार रूप सिंह और सरदार बलवंत सिंह के समक्ष किए गए कथित न्यायेतर इकबालिया बयानों का संबंध है, उन्हें अस्वीकार्य और अविश्वसनीय माना गया। 15 अप्रैल, 1950 को पलविंदर द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने किए गए

कबूलनामे का उपयोग हालाँकि निम्नलिखित कारणों से उसके खिलाफ सबूत में किया गया था।

यह सच है कि सख्ती से माफी देने वाले बयानों को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता है जिसमें कैदी अपने अपराध से इनकार करता है, लेकिन इन बयानों को अक्सर गलत और मनगढ़ंत बताकर दोषी चेतना के परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है।"

यह भी पाया गया कि हालाँकि पलविंदर मोहिंदरपाल के साथ अपनी अवैध साज़िश जारी रखना चाहता था, लेकिन हो सकता है कि वह प्यार की वेदी पर अपनी संपत्ति और पद का त्याग नहीं करना चाहती थी। हो सकता है कि उसका अपने पति को मारने का कोई मकसद रहा हो, लेकिन भरेली के एक भावी प्रमुख की पत्नी के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने का एक मजबूत मकसद था और इस स्थिति में यह किसी भी तरह से असंभव नहीं था कि हत्या मोहिंदरपाल द्वारा अकेले पलविंदर की सहमति और जानकारी के बिना की गई थी, और हालांकि पलविंदर के साथ एक मजबूत संदेह जुड़ा हुआ था, लेकिन विश्वास के साथ यह कहना असंभव था कि उसके द्वारा जहर दिया गया था। इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत दोषी ठहराना संभव नहीं था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोप के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य वह स्वीकारोक्ति थी जो पलविंदर ने 15 अप्रैल, 1950 को की थी और इस स्वीकारोक्ति को, हालांकि वापस ले लिया गया था, इस बिंदु पर स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई थी और आरोप स्थापित किया गया था।

उच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे सामने कई आधारों पर आपत्ति जताई गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया गया कि पलविंदर कौर से विस्तार से पूछताछ करते हुए उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया और धारा सिंह के मामले (1) में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय कानूनी रूप से गलत था, कि अपीलार्थी का एक दोषमुक्त बयान होने का कथित स्वीकारोक्ति, साक्ष्य में अस्वीकार्य था और उसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता था, कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा अधिकांश भौतिक विवरणों में इसका खंडन किया गया था और यह गलत था और किसी भी मामले में इसका टुकड़ों में उपयोग नहीं किया जा सकता था; कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1 और 201 के तहत अपराध, दो अलग-अलग समय पर किए गए अलग-अलग अपराध हैं और अलग-अलग लेनदेन होने के कारण, अपीलकर्ता ने कहा। इच्छमी सहयोगी स्वभाव के थे और उच्च न्यायालय ने बिना किसी पुष्टि के उनकी गवाही पर भरोसा करने में गलती की; कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों पर विश्वास नहीं किया और यह अभिनिर्धारित किया कि "उन्हें मामले में गलत तरीके से पेश किया गया था, जांच में अत्यधिक देरी होने और कहानी विभिन्न चरणों में विकसित होने के कारण, उच्च न्यायालय को उसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था; और अंत में कि अपीलार्थी के खिलाफ साबित हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के टुकड़े कई निर्दोष स्पष्टीकरणों के अनुरूप थे और इसलिए उच्च न्यायालय ने उन संभावनाओं को खारिज किए बिना उन पर भरोसा करने में गलती की।

अपील का निर्णय, हमारे विचार में, एक बहुत ही संकीर्ण दिशा के भीतर निहित है और हमारे सामने तर्क किए गए सभी बिंदुओं पर उच्चारण करना आवश्यक नहीं है। हमारे फैसले में, सकारात्मक रूप से यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जसपाल की मृत्यु पोटेशियम साइनाइड के कारण हुई थी और ऐसा होने पर, भारतीय

दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप भी विफल होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचते हुए न केवल संदेह और अनुमानों पर बल्कि अस्वीकार्य साक्ष्य पर भी कार्रवाई की।

जिस परिस्थिति में जसपाल की मृत्यु हुई वह हमेशा रहस्य में डूबी रहेगी और अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर उन्हें उजागर करना संभव नहीं है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि मोहिंदरपाल ने पलविंदर की जानकारी या सहमति के बिना उसकी हत्या कर दी थी और यह घटना घर पर नहीं बल्कि बलदेवनगर शिविर में हुई थी और मोहिंदरपाल ने अकेले शव का निपटान किया था और पलविंदर का इकबालिया बयान पूरी तरह से गलत है और "मिलाप" में जारी विज्ञापन में जहां तक उसका संबंध था, तथ्यों को सही ढंग से दर्शाया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य "ऐसे चरित्र का है कि उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है और इससे कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। सत्र न्यायाधीश की टिप्पणी, कि परिणामों से निश्चित रूप से पता चला था कि न्याय हमेशा धन और अन्य सांसारिक संसाधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता था और यह मामला शायद इतिहास में सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक के रूप में जाना जाएगा क्योंकि इसमें शामिल पक्ष और जिस वीभत्स तरीके से हत्या की गई थी, वह एक ऐसी मानसिकता का खुलासा करता है जो आवश्यक रूप से न्यायिक नहीं है। न्यायिक निर्णय में भावुकता लाना अनावश्यक था। उच्च न्यायालय इस सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि पलविंदर उसके पति की हत्या के लिए जिम्मेदार था, क्या जसपाल ने आत्महत्या कर ली या गलती से दिए गए जहर से उसकी मृत्यु हो गई या क्या उसे अपीलार्थी द्वारा या मोहिंदरपाल द्वारा या दोनों द्वारा जहर दिया गया था, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित छोड़ दिए गए हैं। पक्षकारों की स्थिति और मामले की देर से की गई जांच और इससे पैदा हुई सनसनी को देखते हुए,

निचली अदालतों के लिए यह बिल्कुल आवश्यक था कि वे संदेह के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालने के खतरे से खुद को बचाएं, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। हमें ऐसा लगता है कि निचली अदालत और कुछ हद तक उच्च न्यायालय उसी त्रुटि में पड़ गए, जिसके खिलाफ बैरन एल्डरसन ने रेग बनाम हॉज (1) में चेतावनी दी थी, जहां उन्होंने इस प्रकार कहा थाः -

"मन एक-दूसरे के लिए परिस्थितियों को अनुकूलित करने में आनंद लेने के लिए उपयुक्त था, और यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें थोड़ा तनाव देने में भी, एक जुड़े हुए पूरे के भागों को बनाने के लिए मजबूर करने के लिए; और व्यक्ति का मन जितना अधिक सरल था, उतनी ही अधिक संभावना थी कि इस तरह के मामले को देखते हुए, अपनी पहुंच को कम करने और खुद को गुमराह करने के लिए, कुछ छोटी सी कड़ी प्रदान करने के लिए जो वांछित है, अपने पिछले सिद्धांतों के अनुरूप कुछ तथ्य को हल्के में लेने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक है।

हमें हाल ही में नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (') में इस बिंदु पर जोर देने का अवसर मिला था। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि कोई अपराध किया गया है जो पर्याप्त नहीं है, कि आरोपी को पता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि ऐसा अपराध किया गया था, और अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से आवश्यक जानकारी के साथ उसके साक्ष्य गायब हो जाते हैं या ऐसे अपराधों के संबंध में गलत जानकारी देते हैं जो जानते हैं या मानते हैं कि यह गलत है। इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के लिए यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना आवश्यक था कि जसपाल की मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा पोटेशियम साइनाइड देने के कारण हुई थी (अपीलार्थी को इस आरोप से बरी कर दिया गया था) और उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि यह इस तरह से हुआ था और उस जानकारी के साथ उसने शव को

छिपाने और निपटाने में भाग लिया था। इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। निम्नलिखित तथ्य, कि जसपाल की मृत्यु हो गई थी, कि उनका शरीर एक ट्रंक में पाया गया था और एक कुएं से पाया गया था और कि अपीलार्थी ने शरीर के निपटान में भाग लिया था, उनकी मृत्यु के कारण या जिस तरीके और परिस्थितियों में यह हुआ, उसे स्थापित नहीं करते हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा पोटेशियम साइनाइड दिया गया था। इस सवाल का सबसे अच्छा सबूत उस डॉक्टर का होगा जिसने पोस्टमॉर्टम किया था। उस साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि जसपाल की मृत्यु पोटेशियम साइनाइड देने के परिणामस्वरूप हुई थी। दूसरी ओर, डॉक्टर की राय थी कि कोई सकारात्मक पोस्टमॉर्टम संकेत नहीं थे जो जहर का संकेत दे सकते थे। उन्होंने कहा कि पोटेशियम साइनाइड क्षयकारी जहर होने के कारण, हाइपरमिया, कोमलता और गैस्ट्रो-आंतों के पथ के व्रण का उत्पादन करेगा और इस मामले में उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं देखे। उन्होंने आगे कहा कि पोटेशियम साइनाइड होंठ और मुंह को खराब कर देता है, और इनमें से कोई भी संकेत शरीर पर नहीं था। इसलिए यह प्रमाण यह साबित करने के बजाय कि मृत्यु पोटेशियम साइनाइड के प्रशासन के कारण हुई थी, इस तथ्य को नकारात्मक बनाता है।

उच्च न्यायालय ने पंजाब को इस तथ्य को साबित करने के लिए 15 अप्रैल, 1950 को पलविंदर द्वारा किए गए इकबालिया बयान पर भरोसा जताया। स्वीकारोक्ति इन शब्दों में है

> "मेरे पति जसपाल सिंह को शिकार के साथ-साथ फोटोग्राफी का भी शौक था। वह जो भी खाल (खाल) घर लाते थे, उनका शिकार करने से उन्हें उन्हें रंगने का शौक हो गया। उन्होंने उत्सुकता से फोटो धोने का काम भी करना शुरू कर दिया। दिसंबर, 1949 में एक दिन,

जसपाल सिंह ने मेरे चचेरे भाई (ताई के बेटे) मोहिंदरपाल सिंह से कहा कि उन्हें फोटो धोने के लिए सामग्री दें। उन्होंने (मोहिंदरपाल सिंह) हरनाम सिंह से कहा, जो बलदेवनगर में प्रधान लिपिक हैं। शिविर, उसी को छावनी से लाने के लिए। हरनार्न सिंह कैंटीन में गए और लौटने पर कहा कि फोटो धोने की सामग्री केवल एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के पास हो सकती है। उन्होंने मोहिंदरपाल सिंह से ऐसा कहा, जिन्होंने कहा कि हरनाम सिंह को उनका नाम लेना चाहिए और दवा लेनी चाहिए। मैंने यह दवा अपने पास रखी। जैसे ही दवा कागज से चिपक रही थी, मैंने उसे एक छोटी सी बोतल में पानी में डाल दिया और अलमारी में रख दिया। उन दिनों मेरे पति अंबाला में थे और मैं उनके साथ शहर की कोठी में रहता था। वह 2-3 दिनों तक शिकार करने गया और वहाँ उसे पेट में तकलीफ होने लगी और वह शुद्ध होने लगा। उन्होंने डॉ. बोहन सिंह से तीन-चार दिनों के लिए दवा भेजी। एक दिन मैंने उसकी दवा की बोतल को अलमारी में रखा जहाँ फोटो धोने के लिए दवा रखी हुई थी। मैं बाहर बैठा हुआ था और जसपाल सिंह ने मुझसे पूछा कि उनकी दवा कहाँ है। मैंने उसे बताया कि यह अलमारी में है। गलती से उन्होंने वह दवा ले ली जो फोटो धोने के लिए थी। उस समय, वह नीचे गिर गया और मेरा छोटा बेटा उसके बगल में खड़ा था। उसने कहा 'मामा, पापा गिर गए थे'। मैं अंदर गया और देखा कि वह पीड़ा में था और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मैं मोहिंदरपाल सिंह के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कि जसपाल सिंह के पिता आ चुके हैं और उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने उसे नहीं

बताया, क्योंकि उसके बेटे और मेरे साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। डर से मैंने उसकी लाश को एक डिब्बे में रख दिया और मोहिंदरपाल सिंह ने ऐसा करने में मेरी मदद की। चार-पाँच दिनों तक डिब्बे मेरी कोठी में रहे। इसके बाद मैंने मोहिंदरपाल सिंह से कहा कि अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने मेरे नौकरों की मदद से मेरी कोठी से उस डिब्बे को हटा दिया और उसे अपनी जीप में रखते हुए बलदेवनगर कैंप में अपनी दुकान पर गए और उसे वहीं रख दिया। वह डिब्बा वहाँ 8-10 · दिनों तक रहा। इसके बाद एक दिन मैं शिविर में गया और वहाँ से ट्रंक को जीप में डाल दिया और मोहिंदरपाल सिंह के साथ जाकर मैंने उसे छत बानूर के पास एक कुएं में फेंक दिया। मुझे वह तारीख याद नहीं है जब जसपाल सिंह ने गलती से दवा ले ली थी। शायद यह जनवरी, 1950 की बात है।

समग्र रूप से पढ़ा गया कथन एक उत्तेजक चरित्र का है। यह किसी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अपराध को करने का सुझाव या साबित नहीं करता है। यह न केवल उसे अपराध करने से छूट देता है, बल्कि मोहिंदरपाल को भी छूट देता है। इसमें कहा गया है कि जे की दोस्त के रूप में मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी. बयान स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं है और इस प्रकार सबूत में अस्वीकार्य है। नारायणस्वामी बनाम सम्राट (1) में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा यह देखा गया था कि साक्ष्य अधिनियम में उपयोग किए गए "स्वीकारोक्ति" शब्द का अर्थ किसी अभियुक्त के बयान के रूप में नहीं लिया जा सकता है जो इस निष्कर्ष का सुझाव देता है कि उसने अपराध किया है। एक स्वीकारोक्ति को या तो अपराध के संदर्भ में स्वीकार करना चाहिए, या किसी भी तरह से उन सभी तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए जो अपराध का गठन करते हैं। एक गंभीर रूप से दोषपूर्ण तथ्य की स्वीकृति, यहां तक कि

एक निर्णायक रूप से दोषपूर्ण तथ्य, अपने आप में एक स्वीकारोक्ति नहीं है। एक बयान जिसमें आत्म-व्याख्यात्मक विषय शामिल है, एक स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं हो सकता है, यदि छूट देने वाला बयान किसी तथ्य का है, जो यदि सच है, तो कथित अपराध को स्वीकार करने के लिए नकारात्मक होगा। कानून के इस दृष्टिकोण में उच्च न्यायालय ने पलविंदर के बयान को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण सबूत के रूप में मानने में गलती की थी। विद्वान न्यायाधीशों ने अपने निर्णय के एक भाग में कहा कि सख्ती से, छूट देने वाले बयानों को बोलने में जिसमें कैदी अपने अपराध से इनकार करता है, उसे स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता है, लेकिन आगे कहा कि इस तरह के बयानों को अक्सर गलत और मनगढ़ंत साबित करके दोषी चेतना के परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत सम्मान के साथ हम इन टिप्पणियों के अर्थ का पालन करने में सक्षम नहीं हुए हैं और अभियोजन पक्ष के लिए बार में उपस्थित विद्वान वकील यह समझाने में असमर्थ थे कि इन शब्दों ने वास्तव में क्या संकेत दिया है। बयान एक स्वीकारोक्ति नहीं होने के कारण और एक दंडात्मक प्रकृति का होने के कारण जिसमें कैदी द्वारा अपराध से इनकार किया गया था, इसका उपयोग मामले में उसके अपराध को साबित करने के लिए सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता था।

न केवल उच्च न्यायालय ने पलविंदर के कथित स्वीकारोक्ति को मामले में सबूत के रूप में लेने में गलती की, बल्कि यह पता लगाने के बाद कि इसका बाकी हिस्सा गलत था, इसके एक हिस्से को स्वीकार करने में भी गलती हुई। इसने कहा कि यह बयान कि मृतक ने गलती से जहर ले लिया था, सरल कारण के लिए विचार से बाहर होना चाहिए। कि यदि मृतक ने गलती से जहर ले लिया होता तो पक्षों का आचरण पूरी तरह से अलग होता। और यह कि वह तब उसके बगल में भागती और शोर मचाती और तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए भेजती; यह अविश्वसनीय था कि यदि मृतक ने

गलती से जहर ले लिया होता, तो उसकी पत्नी चुपचाप खड़ी रहती और उसे मरने देती। इस प्रकार न्यायालय ने उस कथन के आक्षेपात्मक भाग को स्वीकार कर लिया और दंडात्मक भाग को खारिज कर दिया। ऐसा करने में यह स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति के उपयोग के संबंध में अच्छी तरह से स्वीकृत नियम का उल्लंघन करता है कि इन्हें या तो समग्र रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए या समग्र रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और यह कि अदालत छूट देने वाले हिस्से को स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय के रूप में अस्वीकार करते हुए केवल आक्षेप करने वाले हिस्से को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में सम्राट बनाम बालमाकुंड (') मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है, जिन टिप्पणियों के साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं. स्वीकारोक्ति में दो तत्व शामिल हैं, क) अभियुक्त ने महिलाओं की हत्या कैसे की, और (ख) ऐसा करने के लिए उसके कारणों का विवरण, पहला तत्व दोषारोपण करने वाला और दूसरा दोषमुक्ति देने वाला और पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्न थाः क्या अदालत, यदि यह राय है कि उपदेशक भाग विश्वास की सराहना करता है और उपदेशक भाग स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय है, तो पहले वाले पर कार्रवाई कर सकता है और बाद वाले पर कार्रवाई करने से इनकार कर सकता है? संदर्भ का उत्तर यह था कि जहां पुष्टि करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि स्वीकारोक्ति में उपदेशक तत्व का कोई भी हिस्सा गलत है, तो अदालत को स्वीकारोक्ति को समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए और केवल उपदेशक तत्व को स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से अस्वीकार करते हुए स्वीकार नहीं कर सकता है. पलविंदर का कथित स्वीकारोक्ति पूरी तरह से एक उपचारी प्रकृति का है और किसी भी अपराध के अपराध को स्वीकार नहीं करता है। जिन संदिग्ध परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाएगा, वे बयान के उस हिस्से में निहित थे जो मृत शरीर के निपटारे से संबंधित था. बयान के इस हिस्से को यह मानते हुए सबूत के रूप में

इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था कि पहला हिस्सा जो एक उत्तेजक चरित्र का था, गलत था, जब यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि यह ऐसा था, और एकमात्र सामग्री जिस पर इसे इस तरह से आयोजित किया जा सकता था, वह उसी बयान के बाद के हिस्से में उल्लिखित आचरण था और स्वीकारोक्ति के पहले भाग के साथ असंगत बताया गया था।

इसलिए परिणाम यह है कि पलविंदर द्वारा दिए गए और कथित स्वीकारोक्ति में निहित बयान का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है और जिसे उच्च न्यायालय ने यह साबित करने के लिए मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत माना कि जे. असपाल की मृत्यु जहर देने या किसी अपराध के परिणामस्वरूप हुई थी। एक बार जब इस स्वीकारोक्ति को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है, तो यह मानने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जसपाल की मृत्यु पोटेशियम साइनाइड के सेवन के परिणामस्वरूप हुई थी।

उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जो इसके अनुसार यह स्थापित करता है कि जसपाल की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, निम्नलिखित प्रकृति का हैः कि पलविंदर और मोहिंदरपाल का उद्देश्य मृतक से छुटकारा पाना था क्योंकि वह मोहिंदरपाल के साथ चल रही थी। मकसद, भले ही मामले में साबित हो जाए, लेकिन यह साबित नहीं कर सकता कि किस परिस्थिति में जसपाल की मृत्यु हुई या किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। यह एक तटस्थ चरित्र की परिस्थिति है कि मोहिंदरपाल के पास पोटेशियम साइनाइड की मात्रा साबित हुई थी और वह इसे मृतक को देने की स्थिति में था। मोहिंदरपाल द्वारा पोटेशियम साइनाइड को जसपाल के शरीर में पाए बिना केवल यह स्थापित नहीं किया जा सकता है कि उनकी मृत्यु इस घातक जहर के कारण हुई थी। किसी भी मामले में, परिस्थिति ऐसी नहीं है जो अपीलार्थी की निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत हो। उच्च न्यायालय द्वारा पलविंदर के कथित स्वीकारोक्ति के बाद के हिस्से की पुष्टि करने के रूप में संदर्भित अन्य साक्ष्य, जो हमने मामले के

दृष्टिकोण से लिया है, किसी भी चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यदि स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है, तो इसकी पुष्टि करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

श्री सेठी ने तर्क दिया कि कथित स्वीकारोक्ति में निहित बयान अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य द्वारा पुष्टि किए जाने के बजाय विरोधाभासी हैं और स्वीकारोक्ति असत्य साबित हुई है। इस मामले पर चर्चा करना अनावश्यक है क्योंकि हमने इस मामले को लिया है।

परिणाम यह है कि हम यह मानने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सामग्री नहीं है कि जसपाल की मृत्यु पोटेशियम साइनाइड के सेवन के कारण हुई थी। अगर हम रक्षा संस्करण पर विश्वास करते हैं तो उनकी मृत्यु एक दुर्घटना का परिणाम थी। यदि उस संस्करण पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो उनकी मृत्यु के कारण के बारे में कोई सबूत नहीं है। जिस तरीके और तरीके से जसपाल के शव से निपटा गया और उसका निपटारा किया गया, उससे कुछ संदेह पैदा होता है, लेकिन इन तथ्यों से एक सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि उसकी मृत्यु एक अप्राकृतिक मृत्यु थी। ऐसे मामले ज्ञात नहीं हैं जहां मृत्यु आकस्मिक है और आरोपी ने शव के निपटारे के संबंध में एक अजीब तरीके से काम किया है, जिसके कारण वह खुद को अच्छी तरह से जानता है। उनमें से एक यह भी हो सकता है कि उन्हें अपने खिलाफ झूठा मामला शुरू होने का डर था। व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को केवल संदेह पर खतरे में नहीं डाला जा सकता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, और उन्हें केवल निश्चित प्रमाण के आधार पर ही इनसे वंचित किया जा सकता है। इस मामले में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया, न केवल पुलिस उप-निरीक्षक और पुलिस कांस्टेबल और अन्य गवाह जानबूझकर झूठ बोलने के दोषी थे, बल्कि अभियोजन पक्ष अपने झूठ का समर्थन करने के लिए मामले में गवाहों को पेश करने में दोषी था और ऐसा होने पर,

हम महसूस करते हैं कि अपीलार्थी को उस सामग्री पर दोषी ठहराना असुरक्षित होगा जो गलत, झूठे और अस्वीकार्य साक्ष्य को समाप्त करने के बाद बची है।

ऊपर दिए गए कारणों से हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार करते हैं और उसे उस आरोप से भी बरी कर देते हैं।

अपील की अनुमति दी गई।

अपीलार्थी का अभिकर्ताः सरदार बहादुर।

प्रत्यर्थी का अभिकर्ताः पी. ए. मेहता।

कैविएटर के एजेंटः हरबंस सिंह।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक मनीष शर्मा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।